1	2	3
4	Inter-Ministerial Expert Group on Guaranteeing title to Land and its adoption in India	19.3.1991
5	High Power Expert Committee to review IRDP under the Chairmanship of Shri D.R. Mehta, Dy. Governor, RBI	29.9.1996
6	Expert Committee for formulating suitable technical guidelines for implementation of Rural Sanitation Programmes	29.3.1994
7	Expert Committee to advise the Ministry on Concurrent Evaluation of Rural Development Programme	27.7.1994
8	Task Force on preparation of Modules for Distance Education and Post Literacy Campaign	16.12.1993

Area cavered under Wasteland Development Scheme

759. SHRI GOPAL SINH G. SOLANKI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the total area brought under the Wastelond Development Scheme during the years 1992-93, 1993-94 and so far in 1994-95 in Baroda, Surat, Bharuch and Panchmahal districts;

(b) the total amount earmarked and spent for the Development of Wasteland, district-wise;

(c) whether the unspent amount is carried over to the next year; and

(d) if so, the details thereof, district-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WASTELANDS DEVELOPMENT) (COL. RAM SINGH): (a) and (b) The Department of Wastelands Development has approved a project in Panchmahal District under its scheme of "Integrated Wastelands Devedopment Projects" at an outlay of Rs. 2.87 crores for the treatment of 3370 hectares. No project under any schemes of National Wastelands Development Board have been approved for the districts of Bharuch, Baroda and Surat. The budget head of the Department of Wastelands Development is "Wastelands Development" but there is no scheme titled "Wasteland Development Scheme" under imlementation.

(c) Yes, Sir.

(d) For 1993-94, in the case of Integrated Wastelands Development Project Scheme for Panchmahal District, a sum of Rs. 55.90 lakhs was carried forward for utilisation during 1994-95.

अविकसित और अगम्य क्षेत्रों के विकास हेतु योजना

760. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के बड़ोदरा, भरूच और पंचमहल जिलों के अविकसित और अगम्य क्षेत्रों के विकास हेतु 2 अक्तूबर, 1993 से 80:20 के अनुपात में राज्य सरकार की सहभागिता से एक योजना आरम्भ की थी ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत जारी की गई धनराशि कई मामलों में अप्रयुक्त पड़ी हुई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) गैर-कृषि मौसम के दौरान 18 से 60 वर्ष की आयु के शारीरिक रूप से सक्षम सभी ग्रामीण गरीबों की दैनिक मजदूरी संबंधी 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सुनिश्चित रोजगार योजना 2 अक्तूबर, 1993 से शुरू की गई थी। सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत निधियां केन्द्र और राज्य के बीच 80:20 के अनुपात में वहन की जाती हैं। प्रारम्भ में यह योजना गुजरात के वदोदरा जिले के 5 खण्डों, भड़ौच जिले के 7 खण्डों, सूरत जिले के 13 खण्डों और पंचमहल जिले के 11 खण्डों, सहित देश के उन सभी खण्डों में लागू की गई थी जहां पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाई जा रही है।

(ख) और (ग) 1993–94 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सहायता के भाग के रूप में वदोदरा जिले को 25 लाख रुपए भड़ौच जिले को 35 लाख रुपए, सूरत जिले को 65 लाख रुपए और पंचमहल जिले को 55 लाख रुपए रिलीज किए गए थे। राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत पंचमहल जिले द्वारा इस्तेमाल न की गई राशि 33.60 लाख रुपए थी जबकि वदोदरा, भड़ौच और सूरत जिलों ने 1993–94 के दौरान "शून्य" खर्च की सूचना दी है। निधियों के इस्तेमाल न करने का मुख्य कारण यह था कि योजना नई थी और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को इससे परिचित होने और इसे लागू करने में कुछ समय लगा।

तथापि कार्य ने अब गति पकड़ ली है और राज्य में फरवरी 1995 तक 20.25 लाख श्रम दिन का रोजगार सृजित करने हेतु 1014.82 लाख रुपए खर्च किए गए हैं संदर्भनाधीन चार जिलों में खर्च और सृजित रोजगार के ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :

जिला	(लाख रु० में) 1994–95 के दौरान फरवरी 95 तक खर्च	(लाख श्रम दिन) सृजित रोजगार
1. बदोदरा	52.10	0.78
2. भडौच	105.83	2.12
3. सूरत	70.74	0.81
4. पंचमहल	251.58	4.82

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पेयजल योजनाओं पर खर्च की गई धनराशि

761. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन तथा त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रमों के अन्तर्गत पेयजल सुविधा के विस्तार के लिए वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान प्रत्येक वर्ष में राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध करवायी गयी ;

(ख) खर्च की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्यवार कितने नलकूपों का खनन किया गया और कितने हैंडपम्प लगाए गए तथा हैंडपम्पों के लगाए जाने के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई; और